

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 114 / 2016 अपील (RCMS/2016/00041)

पंजीयन दिनांक – 08.11.2016

निर्णय दिनांक – 23.04.2019

1. श्रीमती गौतमी उर्फ श्रीमती गौमती बाई पुत्री श्री पोखरलाल पुरोहित ब्राह्मण जरिये मुख्तियार श्री सुरेशचन्द्र पिता श्री रमेशचन्द्र पालीवाल, निवासी-5, राहीनगर, इन्दौर (म.प्र.)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री बंशीलाल पिता श्री औंकारलाल पुरोहित ब्राह्मण, निवासी अरनिया जोशी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय—
 - 1/1 श्री कैलाश पिता स्व. श्री बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी 162, सांवरियानगर (छोटा बांगरडा), बांगरडा रोड, इन्दौर (म.प्र.)।
 - 1/2 श्री पारस पिता स्व. श्री बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी 162, सांवरियानगर (छोटा बांगरडा), बांगरडा रोड, इन्दौर (म.प्र.)।
 - 1/3 श्री दिनेश पिता स्व. श्री बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी 162, सांवरियानगर (छोटा बांगरडा), बांगरडा रोड, इन्दौर (म.प्र.)।
 - 1/4 श्री विकास पिता स्व. श्री बंशीलाल ब्राह्मण, निवासी 162, सांवरियानगर (छोटा बांगरडा), बांगरडा रोड,
 - 1/5 श्रीमती कंचन पत्नि श्री प्रकाश बणोरा, निवासी सुन्दरचा, तहसील व जिला राजसमन्द।
 - 1/6 श्रीमती गुणवन्ती उर्फ शारदा पत्नि श्री राजू जोशी, निवासी सुभाष चौक, पानी की टंकी (खुटाल कॉम्प्लेक्स के पास), इन्दौर (म.प्र.)।
 - 1/7 श्रीमती मोहनी उर्फ मना पत्नि श्री ललित जोशी, निवासी 43 न्यू दुर्गानगर, मरीमाता चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)।
 - 1/8 श्रीमती अम्बा बाई पत्नि स्व. श्री बंशलाल पालीवाल, निवासी अरनिया जोशी, हाल मुकाम, 162, सांवरियानगर (छोटा बांगरडा), बांगरडा रोड, इन्दौर (म.प्र.)।
2. सरपंच ग्राम पंचायत अरनिया जोशी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोंडेंट्स

उपस्थिति:—

1. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील अपीलान्ट
2. श्री संजय सेन – वकील रेस्पोंडेंट संख्या-1/1 से 1/2

प्रकरण संख्या-10/2014, श्रीमती गौमती बाई बनाम श्री बंशीलाल व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 23.04.2019

उक्त अपील अपीलान्त द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या-10/2014, श्रीमती गौमती बाई बनाम श्री बंशीलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं-

- अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत अरनिया जोशी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या-205 दिनांक 25.11.1982 के विरुद्ध एक अपील धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम के उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा समक्ष प्रस्तुत की गई और कथन किया कि अपीलान्त के पिता श्री पोखरलाल के तीन पुत्रियां भागीरथी, शशि एवं गौमती बाई हुई। मौजा अरनिया जोशी में श्री पोखरलाल की पुश्तैनी भूमि आराजी संख्या-22, 23/1, 24, 27, 43, 44, 45, 74, 130, 15 कुल रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 43, 44, 49, 50, 130, 139, 142, 23, 3, 18, 22, 23/1, 24, 27, 45, 522/24, 561/82, 569/107, 231/2 स्थित है। उक्त आराजीयात में अपीलान्त का जन्म से ही हित निहित है। अपीलान्त के हक हिस्से व आधिपत्य की होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत अरनिया जोशी के द्वारा पोखरलाल का विरासत का नामान्तरकरण संख्या-205 दिनांक 25.11.1982 श्री बंशीलाल के नाम दर्ज कर दिया जबकि नामान्तरकरण अपीलान्त के नाम स्वीकृत किया जाना था। अपीलार्थी द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर कथन करते हुए नामान्तरकरण संख्या-205 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को मयाद बाहर मानते हुए, अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, निम्बाहेडा के निर्णय दिनांक 19.09.2016 एवं श्रीमती गौमती की अनुपस्थिति में रेस्पॉण्डेंट के कथनों का समर्थन करते हुए निर्णय दिनांक 05.10.2016 पारित कर अपील अपीलान्त खारिज की।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉण्डेंट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्त व वकील रेस्पॉण्डेंट संख्या-1/1 व 1/2 उपस्थित, अन्य अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 16.04.2019 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्त ने अपील एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री पोखरलाल की मृत्यु उपरान्त अपीलान्त को कोई सूचना दिया बिना सरपंच श्री ऊंकारलाल द्वारा अपने पुत्र श्री बंशीलाल को श्री पोखरलाल का गोदीना पुत्र बताकर पोखरलाल की जायदाद को अवैध तरिके से पाने की नियत से बंशीलाल के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया। नामान्तरकरण से पूर्व अपीलान्त को कोई सूचना नहीं दी गई, उसका पक्ष नहीं सुना गया, न ही नोटिस जारी किया गया। नामान्तरकरण बिना कोरम के स्वीकृत करवा लिया गया। बंशीलाल के गोदी पुत्र होने के सम्बन्ध में कोई लिखित गोदीनामा नहीं लिखा गया, न ही कोई पंजीकृत गोदीनामा प्रस्तुत किया गया। राजस्व न्यायालय को गोद का बिन्दु तय करने का कोई अधिकार नहीं है तथा गोद के आधार पर उसका म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व अपीलान्त को कोई सूचना नहीं दिये जाने यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है कि उसे इस प्रकार के अवैध नामान्तरकरण की जानकारी हो। जैसे ही नामान्तरकरण की जानकारी हुए, नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत करते समय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर कोई विचार न कर मयाद प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर निर्णय पारित किया जो काबिल निरस्त है। इस मामले में रेस्पोंडेंट संख्या-1 द्वारा शशी और भागीरथी को अपने साथ मिलाकर अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील से अपना नाम विलोपित करवा दिया। श्रीमती गौमती द्वारा अपने पुत्र श्री सुरेश के नाम पॉवर ऑफ एटोर्नी दिनांक 08.07.2016 को जारी की और उसे केस लडने हेतु मुकर्रर किया जिसकी प्रति अपील के साथ संलग्न है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, निम्बाहेडा के निर्णय दिनांक 19.09.2016 को भी आधार मानते हुए अपील अपीलान्त को निरस्त की। उक्त निर्णय दिनांक 19.09.2016 के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, निम्बाहेडा समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश नियम 09 नियम 13 दीवानी प्रकरण संहिता का पेश किया जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2016 स्वीकार कर उनके विरुद्ध उक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2016 को अपास्त की एवं मूल प्रकरण का पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिनांक 21.05.2018 को पारित किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने जिस निर्णय दिनांक 19.09.2016 को आधार बनाकर अपील निरस्त की वह निर्णय अपास्त हो चुका है।

इस मामले में रेस्पोंडेंट संख्या-2 सरपंच श्री ऊंकारलाल द्वारा नामान्तरकरण आदेश पर लिखा जाना था कि बंशीलाल मेरा जायन्दा पुत्र है, इस कारण नामान्तरकरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता और पत्रावली तहसीलदार को स्थानान्तरित की जानी थी। परन्तु उसके द्वारा अपीलान्त को कोई सूचना नहीं देकर नामान्तरकरण अपने पुत्र श्री बंशीलाल के नाम स्वीकृत कर दिया जो एबनिश्योवोर्ड होकर बिना अधिकार के है।

रेस्पोंडेंट ने जानबूझकर दावा बाद में किया है क्योंकि वह जानता है कि अपील में कथित म्यूटेशन निरस्त हो जायेगा इस कारण अपील का पता चलते ही यह वाद पेश

किया गया तथा इस वाद में एकतरफा निर्णय व डिक्री अपास्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में म्यूटेशन निरस्त किया जाना आवश्यक है।

श्री बंशीलाल के कहे अनुसार उसे गोदी पुत्र लिया गया था अगर इस तथ्य को मान भी लिया जावे तो उसे अपने पिता सरपंच ऊंकारलाल के जायन्दा पैतृक हक का कोई अधिकार नहीं रहता है जबकि वह गोदीना पुत्र नहीं होने से ही उसे जायन्दा पिता का वारिस की हैसियत से पिता के स्वर्गवास के बाद जमीनें खाते हुई है तथा नामान्तरकरण की नकल वर्ष 2004 में पेशी गई तब बंशीलाल ने बदनियतीपूर्वक अपने प्राकृतिक पिता ऊंकारलाल के हक व हिस्से से आयी पैतृक सम्पत्ति में अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से का त्याग दिनांक 20.06.2014 को किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि बंशीलाल कभी भी पोखर जी का गोदीना पुत्र नहीं रहा। बंशीलाल को गोदी पुत्र लिये जाने के सम्बन्ध में और बंशीलाल का नामान्तरकरण किस आधार पर किया गया उसके सम्बन्ध में जानकारी ग्राम पंचायत अरनिया जोशी से मांगी गयी जिस पर अपीलान्त को जानकारी हुई कि इन्तकाल खोलने के लिए बंशीलाल द्वारा इसी तरह का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। साथ ही भागीरथी बाई एवं शशीबाई, गोमती बाई पुत्री पोखरलाल जी व टक्कूबाई बेवा पोखरलाल की सहमति रेकॉर्ड पर नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि बंशीलाल ने अपने जायन्दा पिता ऊंकारलाल जी जो तत्कालीन सरपंच थे, के पद का नाजायज फायदा उठाकर यह बिना किसी दस्तावेजी आधार के नामान्तरकरण करवाया जो खारिज किए जाने योग्य है, साक्ष्य में ग्राम पंचायत अरनिया जोशी द्वारा जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। श्री बंशीलाल के नाम एक एफआईआर संख्या-5/2016 में उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी माना गया कि बंशीलाल द्वारा समय समय पर अपने पिता के नाम को स्वयं की सहूलियत के हिसाब से बदला गया है। इनसे यह सिद्ध होता है कि श्री बंशीलाल श्री पोखरलाल का कभी भी गोदपुत्र नहीं था और उसके नाम स्वीकृत नामान्तरकरण पूर्णतया अवैध है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिनांक 05.10.2016 अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावें और नामान्तरकरण अपीलान्त के पक्ष में स्वीकृत कराये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा न्यायिक दृष्टांत (RRD 1985 P. 99, RRD 1984 P. 174, RLW 1997 (1) Raj P. 226, RBJ (7) 2000 P. 546) प्रस्तुत किए।

विद्वान वकील रैस्पोंडेंट संख्या-1/1 से 1/2 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कथनों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलान्त की अन्य दोनों बहनों ने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष यह तथ्य स्वीकार किया है कि उन्होंने कभी भी श्री सुरेश के नाम मुख्तियार नामा निष्पादित नहीं किया जिससे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील विद्रो की जावें और उनका आवेदन स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उनके नाम अपील से विलोपित किए गए। दोनों बहनों से यह भी माना है कि बंशीलाल को समस्त रितीरिवाजों से गोदपुत्र माना गया है और उक्त जमीन पर उसका कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्री गौतमी उर्फ गौमती कभी भी उपस्थित नहीं हुई जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया कि पांवर ऑफ एर्टोनी जारी नहीं की गई। ऐसी स्थिति में ग्राम

पंचायत अरनिया जोशी द्वारा बंशीलाल को बहैसियत गोदीपुत्र मानकर निर्णय किया गया नामान्तरकरण बिल्कुल सही है। पोखरलाल की तीनों पुत्रियों को इसकी पूर्ण जानकारी थी और तत्समय उनके द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया, जिससे भी उनकी सहमति प्रतीत होती है। फिर भी अपीलान्त द्वारा 32 वर्षों उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय समक्ष मयाद बाहर अपील पेश की गई और अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का निरस्त किया गया। उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, निम्बाहेडा में वाद संख्या-19/2015 में निर्णय दिनांक 19.09.2016 को पारित किया जिसमें श्री बंशीलाल को श्री पोखर जी गोदीपुत्र घोषित किया है। हालांकि उक्त निर्णय दिनांक 19.09.2016 माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, निम्बाहेडा द्वारा अपास्त किया जाकर मूल प्रकरण पुनः दर्ज करने का आदेश दिनांक 21.05.2018 को पारित किया अतः मूल प्रकरण रिस्टोर होकर विचाराधीन है। प्रश्नगत प्रकरण में दौराने अपीलीय प्रक्रिया विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 का पेश कर दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं परन्तु प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र मान्य नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या-1/1 व 1/2 द्वारा न्यायिक दृष्टांत (RRT 2016(2) P. 1139, RRT 2009(1) P. 488, RRT 2018 (2) P. 1026) प्रस्तुत किए।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की लिखित एवं मौखिक बहस व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों पर ससम्मान मनन किया तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपील 32 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत करने का प्रश्न है, जिस पर अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या-1/1 व 1/2 द्वारा भी आपत्ति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्यों के विश्लेषण से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि नामान्तरकरण संख्या 205 पारित किये जाने समय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने दौरान, कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में इस निर्णय के आगे के पेश में विस्तृत विवेचन भी किया है, जो प्रासंगिक बिन्दु से सुसंगत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिप्रादित किया है कि देरी माफी के लिये लचीला रुख रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि देरी को माफ नहीं करने से कई महत्वपूर्ण बिन्दु न्याय से वंचित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मामला गुणावगुण पर विचारण योग्य होने से एवं सुलभ न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अपीलान्त द्वारा जानबुझकर देरी की। ऐसी स्थिति में उक्त अपील की मियाद को माफ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और प्रकरण का गुणावगुण पर विनिश्चय करना उचित है।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने अपीलिय प्रक्रिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जा.दी. का प्रस्तुत कर दस्तावेज पेश किये जिस पर अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या-1/1 व 1/2 द्वारा आपत्ति जाहिर की। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत अरनिया जोशी द्वारा सूचना के अधिकार अन्तर्गत जारी पत्र, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की प्रति, अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, निम्बाहेडा के आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की है, जो प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जा.दी. स्वीकार योग्य है एवं उक्त दस्तावेज न्यायालय के आदेशों की प्रतियां होने से उनकी सत्यता पर प्रश्न करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

मौजा अरनिया जोशी में श्री पोखरलाल की पुश्तैनी भूमि आराजी संख्या-22, 23/1, 24, 27, 43, 44, 45, 74, 130, 15 कुल रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 43, 44, 49, 50, 130, 139, 142, 23, 3, 18, 22, 23/1, 24, 27, 45, 522/24, 561/82, 569/107, 231/2 स्थित है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत अरनिया जोशी के द्वारा पोखरलाल का विरासत का नामान्तरकरण संख्या-205 दिनांक 25.11.1982 श्री बंशीलाल के नाम गोद पुत्र की हैसियत से दर्ज कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व सम्पत्ति के अर्जन एवं पोखरलाल के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई। न ही अपीलान्ट व अन्य को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। अपने कथन के समर्थन में अपीलान्ट की ओर से ग्राम पंचायत अरनिया जोशी द्वारा जारी पत्र दिनांक 29.09.2015 भी प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार भागीरथी, शशि, गोमती बाई को इन्तकाल से पूर्व या इनके सहमति के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। पंचायत कोरम 30.11.1982 में नामान्तरकरण संख्या-205 से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व विधिक प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में आलौच्य नामान्तरकरण विधि सम्मत प्रतीत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई, जो विधि अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।

उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, निम्बाहेडा में वाद संख्या-19/2015 में निर्णय दिनांक 19.09.2016 को पारित किया जिसमें श्री बंशीलाल को श्री पोखर जी गोदीपुत्र घोषित किया है। उक्त निर्णय दिनांक 19.09.2016 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, निम्बाहेडा समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश नियम 09 नियम 13 दीवानी प्रकरण संहिता का पेश किया जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2016 स्वीकार कर उनके विरुद्ध उक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2016 को अपास्त की एवं मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिनांक 21.05.2018 को पारित किया। अतः मूल प्रकरण रिस्टोर होकर वर्तमान में विचाराधीन है।

दौराने अपील, उपस्थिति अधिवक्ताओं द्वारा श्री बंशीलाल के गोदीपुत्र होने के सम्बन्ध में अपने तर्क प्रस्तुत किए एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों की ओर ध्यान आकृष्ट किये जिनके अवलोकन से तथ्यों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं विवेचन से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 05.10.2016 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, निम्बाहेडा समक्ष लम्बित प्रकरण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का निर्णय दिनांक 05.10.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर, अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, निम्बाहेडा समक्ष लम्बित प्रकरण की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official